भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.02.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 714 का उत्तर

मिशन निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन

714. श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2030 तक मिशन निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे को सहायता प्रदान करने हेतु यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट/इंडिया (यूएसएआईडी/इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौता ज्ञापन भारतीय रेलवे को रेलवे क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान के बारे में बताने और उन्हें साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या समझौता ज्ञापन उपयोगिता आधुनिकीकरण, उन्नत ऊर्जा समाधान और प्रणालियों, क्षेत्रीय ऊर्जा और बाजार से जोड़ने और निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं उनकी सेवाएं लेने, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने हेतु अन्य अंतःक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय रेलवे को डीजल, कोयला आदि जैसे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो क्या इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद मिलने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): 14 जून 2023 को भारतीय रेल (आईआर), भारत सरकार और यूनायटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट/इंडिया (यूएसएआईडी/इंडिया) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत के आकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा

s.k

लक्ष्यों (ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा), जिसमें उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने और जनशक्ति की दक्षता निर्माण के लिए बाजार-आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं, में योगदान करने के यूएसएआईडी/इंडिया और भारतीय रेल के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनके बीच भागीदारी को आगे बढ़ाना है। इस समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा योजना और प्रापण, ऊर्जा दक्षता नीति तैयार करना, विनियामक और कार्यान्वयन बाधाओं का निवारण करने हेतु तकनीकी सहायता और दक्षता निर्माण कार्यक्रम जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

यूएसएआईडी द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी (एसएआरईपी) पहल के अंतर्गत इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता सुलभ कराया जाना अभिप्रेत है।

इस समझौता ज्ञापन की परिधि में अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपायों के परिनियोजन का अभिनिर्धारण करना, उन्हें बढ़ाना और उनमें तेजी लाना शामिल है, जो डीजल, कोयला आदि जैसे आयातित ईंधन पर भारतीय रेल की कम निर्भरता में परिणत होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली के प्रापण और ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था में हरित क्षेत्र में रोजगारों के सृजन की संभावना है। यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का भी सुदृढ़ीकरण करेगा जिससे स्थानीय उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलेगा जो रोजगार सृजन में सहायता करेगा। यह समझौता ज्ञापन पांच साल की कार्यकाल के लिए या यूएसएआईडी/इंडिया के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी (एसएआरईपी) कार्यक्रम के वास्तविक अंत तक प्रभावी है।

****

s.k